society, but the University Grants Commission that was primarily instituted for ensuring academic excellence in the universities has become so big and the impression, today, is that it is a funded institution; it does not reflect adversely on the University Grants Commission. It has worked very nicely and, in no way, as for the present set-up - I have no adverse comment to make - they are doing excellent work. But the Minister is incharge of this very important Department and he represents, in a way, the aspirations of people in the country.

MR. CHAIRMAN: Put your question, please.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: How does he feel sure on the academic excellence in universities because the University Grants Commission may not be able to do that? Will he look into this aspect that the University Grants Commission is expanded? How can he ensures the academic excellence. Is he devising some instrument so that he feels sure that....

MR. CHAIRMAN: That is not the question. ...*(Interruptions)*... Mr. Soz, please put it.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: How will the academic excellence be ensured.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, it does not relate to the main question at all.

MR. CHAIRMAN: Right.

SHRI KAPIL SIBAL: But I want to send a message. ...*(Interruptions)*... I want to send a message to the entire university system, and the message, Sir, is that we are committed to implement the semester system in this country; this is good for the student community, and when we look at education, we look at the students of this country, and not at the teachers. We want the teachers to cooperate for the future generations of this country to absorb and embrace a system which will better the prospects of this country.

Credit rating of MSMEs

*423. DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN:††

SHRI SANTOSH BAGRODIA:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) the number of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), which are awarded credit rating by different agencies every year;

(b) the steps Government is taking to increase their numbers; and

(c) whether Government is planning to advise National Small Industries Corporation (NSIC) to empanel more agencies for credit rating?

---

†† The question was actually asked on the floor of the House by Dr. E.M. Sudarsana Natchiappan

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SHRI DINSHA J. PATEL): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The number of Micro and Small Enterprises (MSEs) awarded rating by different Rating Agencies under Performance & Credit Rating Scheme since inception is given in the table below:-

Sl.No.	Rating Agency	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (Upto Nov., 09)
1.	D&B	466	1356	1800	685	0
2.	CRISIL	149	379	775	2021	2540
3.	SMERA	1	318	715	1333	1401
4.	ONICRA	48	99	547	971	803
5.	FITCH	0	17	13	1	0
6.	ICRA	7	1	0	0	0
7.	CARE	0	0	0	0	0
	TOTAL	671	2170	3850	5011	4744

(b) The scheme is being implemented by NSIC on behalf of the Government of India. Government, through NSIC is creating awareness about the benefits of the scheme by conducting seminars/ workshops etc.

(c) No, Sir.

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: Sir, this credit rating system is a newly proposed one in the UPA-I. In the last five years, I would like to know - because it is a combination of not only the credit but also various other factors of operation, marketing, business, and also risk management - how many numbers in the micro and how many in the small industries had got the certification and how many were successful in this field.

श्री दिन्शा जे. पटेल : माननीय सभापति जी, रेटिंग सिस्टम के बारे में माननीय सदस्य ने जो बताया, वह सही है। 7 अप्रैल, 2005 को क्रेडिट स्कीम की शुरूआत हुई और उस समय जो मंत्री थे, श्री पी. चिदम्बरम जी, उन्होंने रेटिंग सिस्टम शुरू की। रेटिंग सिस्टम micro and small industries को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। उन्होंने इसके अलग-अलग आंकड़े के बारे में पूछा है। मेरे पास small और micro के लिए अलग-अलग आंकड़े नहीं हैं, मगर करीब 15000 से ज्यादा micro and small industries ने रेटिंग का काम करवाया है। उसके लिए जो अलग-अलग 7 कम्पनियां हैं, उनसे वे रेटिंग करवाती हैं। रेटिंग के लिए कोई दबाव नहीं है। उसको NSIC द्वारा मदद दी जाती है और मदद देने में भी ऐसा है कि 25 प्रतिशत पेमेंट करके कोई भी इन्डस्ट्री अपना रेटिंग करवा सकती है। रेटिंग करवाने से यह होता है कि उनको बैंक लोन में बहुत फायदा होता है और उनकी prestige देश और परदेस में बढ़ जाती है। इससे उनको माल बेचने में भी बहुत बड़ा फायदा होता है। इसलिए रेटिंग सिस्टम में

करीब 15000 इन्डस्ट्रीज ने रेटिंग करवायी हैं। यह उन्होंने अलग-अलग एजेंसीज़ के द्वारा करवाया है, क्योंकि यह forcefully नहीं है। इसमें NSIC का जो रोल यह है कि ये इन्डस्ट्रीज 25 प्रतिशत पैसे भर कर रेटिंग करवाती हैं और बाकी का जो 75 प्रतिशत का बिल है, वह NSIC को भेज देती हैं। तब NSIC उसकी स्टडी करके उसमें ज्यादा से ज्यादा 40,000 रुपये देती है। माननीय सदस्य ने जो कहा है, मैं इसके अलग-अलग आंकड़े निकाल कर उनको भेज दूंगा।

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: Sir, since I was told that more than Rs.20 crores have been allocated for this purpose, I would like to know from the hon. Minister whether the Government is conducting any study on focussed areas like availability of credit at attractive interest rates, recognition of global trade, prompt sanction of credit by banks and financial institutions, subsidised rating fee structure for SSIs, facilitating vendors' and buyers' capability assessment of SSIs and enabling the SSIs to ascertain SWOT theory for existing operations taking corrective terms. I would like to know whether these things have been taken into consideration in the past five years and whether any study was done on these things; if not, whether the Government proposes to undertake study on these things.

श्री दिन्शा जे. पटेल : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य जो बात कर रहे हैं, यह प्रश्न रेटिंग के बारे में है। इस देश में करीब 2 करोड़ 60 लाख industries हैं। इनमें 85 प्रतिशत industries ऐसी हैं जो micro and small scale industries हैं और उनमें से केवल 15 प्रतिशत ही रजिस्टर्ड हैं, बाकी रजिस्टर्ड नहीं हैं। बड़ी industries की बात अलग है। इसमें बैंकों से बढ़ी हुई ऋण सीमा को प्राप्त करने की बात है जिसमें उन्हें 23 प्रतिशत उत्तरदायित्व की प्राप्ति हुई है। इसके साथ ही इसमें ऋणों पर मार्जिन मनी में कमी, बैंकों से विभिन्न ऋण सुविधाओं पर बेहतर व सस्ती ब्याज दरें प्राप्त करना है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि उनको ब्याज दरों में half per cent से 1 per cent या डेढ़ per cent की कमी मिल जाती है। उसकी भी स्टडी की गई है। उन्हें बिक्री में करीब 60 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी मिली है, निर्यात बिक्री में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी मिली है और सप्लायर से ऋण की अवधि में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसकी स्टडी भी की गई है। सरकार यह भी स्टडी कर रही है कि छोटे उद्योगों को बढ़ावा कैसे मिले, देश में स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज की ज्यादा से ज्यादा बढ़ोत्तरी कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोज़गार कैसे मिले और जो skilled workers हैं, वे अपनी industries छोटे गांवों में कैसे स्थापित कर सकें। इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें सरकार आगे बढ़ रही है।

श्री शिवानन्द तिवारी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग रोजगार देने का बहुत बड़ा जरिया हैं। इस सेक्टर में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिला है और साथ ही निर्यात के मामले में भी इस क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन, पिछले कई वर्षों से लगातार यह देखा गया है कि बैंकों द्वारा इस क्षेत्र में जो क्रेडिट देने की फैसिलिटी है, वह लगातार घट रही है। यही नहीं, चिन्ताजनक बात यह है कि प्रति इकाई रोजगार देने का जो प्रतिशत था, उसका आकार भी घटा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के प्रति बैंकों का जो रुख है, उसमें बदलाव लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं ताकि उनको वित्तीय सहायता मिल सके और वे ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर सकें?

श्री दिन्शा जे. पटेल : सभापति महोदय, वैसे तो यह प्रश्न इस प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने पहले ही बताया है कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिले, इसके लिए सरकार बहुत सी कोशिशें कर रही हैं,

मेरा डिपार्टमेंट भी बहुत सी कोशिशें कर रहा है। अभी तीन महीने पहले प्राइम मिनिस्टर का सभी इंडस्ट्रीज़ के प्रतिनिधियों, हमारे ऑफिसर्स और एक्सपर्ट्स के साथ करीब एक घंटे तक डिस्कशन हुआ था और प्राइम मिनिस्टर ने immediate एक task force, एक High Power Committee की घोषणा भी कर दी। High Power Committee बनने के बाद उन्होंने उसमें से सात लोगों की एक और कमिटी भी बना दी। माननीय सदस्य ने जो बात बताई है, बैंकों में होने वाले delay के बारे में, वहां scrutiny होने के बाद भी जो application जाती है, उस scrutiny हो चुकी application में भी बहुत delay होता है, इसकी जो High Power Committee कमिटी है, उसके लिए भी यह प्रश्न रखा गया है और उसमें इंडस्ट्रीज़ के प्रतिनिधि को भी रखा गया है, एक्सपर्ट्स को भी रखा गया है और उसकी रिपोर्ट तैयार होकर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास पहुंच गई है और अभी 15-20 दिनों में उस पर डिस्कशन होगा। आपने जिन दिक्कतों के बारे में बताया है, उन दिक्कतों को दूर करने की भी हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी उनको ऋण मिले। वैसे तो यह Finance Deptt. का काम है, संबंधित मंत्री के साथ भी डिस्कशन करके, कैसे हम उसको जल्दी से जल्दी निबटा सकें, इसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं।

श्री विनय कटियार : सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर छोटे उद्योग की एक पहचान थी, जो धीरे-धीरे मिटती चली जा रही है और चीन जैसे देश में, जहां एक समय में बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही थी, छोटे उद्योग के माध्यम से आज भारत के अंदर चीन के उद्योग का बना हुआ सामान छाता चला जा रहा है। क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि भारत के अंदर जिस प्रकार के पुराने उद्योग थे, उन परम्परागत उद्योगों को वे बढ़ावा देने का कोई काम करेंगे? बैंकों द्वारा जो छोटा भी ऋण दिया जाता है, उसमें भी कम से कम 20 या 25% वह बैंक के अंदर कमीशन के रूप में चला जाता है, क्या आप इस पर कोई अंकुश लगाएंगे?

श्री दिन्शा जे. पटेल : सर, वैसे तो यह सारा क्वेश्चन रेटिंग का क्वेश्चन है, फिर भी मैंने बताया कि मेरे आने के बाद स्माल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और यू.पी.ए. सरकार ने इस दिशा में बहुत कोशिश की है। एक High Power Committee के ज़रिए इन सारी प्रॉब्लम्स को निपटाने की हम कोशिश कर रहे हैं और मैंने अभी बताया कि within three months, उसको time bound कर दिया गया है, उसको time limit बता दी गई है कि तीन महीने के भीतर उसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए। उसमें सभी एक्सपर्ट्स को लगाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई किसी एक ही इंडस्ट्री का आदमी है या गवर्नमेंट का है, सभी एक्सपर्ट्स को उसमें लगाया गया है। मैं चाहता हूं कि हमारा देश चाइना से भी आगे बढ़े, भारत देश अपना नाम चाइना से भी आगे बढ़ाए और अव्वल नम्बर पर जैसे अपना पहले नाम था, अपना नाम उसी अव्वल नम्बर पर आए, ऐसी कोशिश भी हम कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि हमारा देश आगे बढ़ेगा और जरूर वह अव्वल नम्बर पर आ जाएगा और छोटी इंडस्ट्रीज़ को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिलेगा।

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, my question is directly linked to the reply which the Minister has made just now. He has told that the rating gives the small scale industries an advantage and also that helps them while getting credit/loans from institutions. He has also replied that till now a majority of the small scale sector is not yet registered and is not rated, around 85 per cent of the small scale sector. Without boosting this 85 per cent of the unrated and unregistered small scale sector, I think the UPA Government cannot properly translate its policy in promoting the small scale sector, if the

rating is made a point. My question to the hon. Minister is this. Definitely, they are making in-depth study for making available credit to the small scale sector. What is the percentage of unrated small scale and micro industries getting bank loans, *vis-a-vis* the rated ones? I would also like to know whether he takes note of the fact that among the small scale and micro sector big segments are also operating as proxy to large scale sector to avail of the advantage of this benefit. It is linked to it.. It is a fact that the rating is also involved in that. A big section of the small scale sector is operating as proxy to the large scale sector. Most of them are rated, and the under-rated are not getting loans. As my colleague has pointed out, the share of the small scale sector loan, in the whole banking credit, is, gradually, going down. So, in this situation, how does the hon. Minister propose to address this issue?

MR. CHAIRMAN: Mr. Sen, your supplementary is longer than the original question.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: My supplementary emanated from the reply of the hon. Minister.

श्री दिन्शा जे. पटेल : सभापति जी, माननीय सदस्य ने इकाइयों के बारे में जो बात कही है, अलग-अलग इकाइयों को यह सूचना दी जाती है। मैंने पहले ही बताया कि रेटिंग का जो मामला है, रेटिंग का मामला कंपलसरी नहीं है, कौन सी इंडस्ट्री ने, कौन सी इकाई ने रेटिंग करवानी है, नहीं करवानी है, यह उनके ऊपर निर्भर करता है। कोई भी छोटी इकाई अपनी रेटिंग करवा सकती है, 25 परसेंट पेमेंट करके वे अपनी रेटिंग करवा सकते हैं। रेटिंग करने के बाद बाकी का जो पैसा है, वह NSIC उनको भेज देती है, ज्यादा से ज्यादा 40,000 रुपए तक NSIC द्वारा दिया जाता है। NSIC के सदस्य उसके ऊपर विचार करके, उनका पेमेंट कर देते हैं। मैं मानता हूं कि सदस्य की जो चिंता है, हमारा डिपार्टमेंट भी वही चिंता कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इकाइयों को इसमें जोड़ा जाए। अभी तक NSIC के साथ 26,000 इकाइयां रजिस्टर्ड हैं। ज्यादा से ज्यादा इकाइयां रजिस्टर होंगी, तो उनको भी मालूम हो सकेगा और portal द्वारा सारी की सारी डिटेल्स उनको पहुंचे, इसका भी इंतजाम किया गया है और छोटे-छोटे गांवों में भी इसका इंतजाम किया गया है कि वहां भी सूचनाएं पहुंचे और जितनी ज्यादा रेटिंग होगी, उतना ही उनका माल बिकेगा, उनकी prestige होगी, उनको बाहर के देशों में prestige मिलेगी, उनको बैंकों में prestige मिलेगी और बैंकों को ज्यादा सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि उनको जो पैसा देना है, यदि रेटिंग वाली कंपनी होगी, तो बैंक वालों को ज्यादा खोजबीन नहीं करनी पड़ेगी, वे अपने आप ही उनको पैसा देंगे। ये सारी कोशिशें हम कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि हम जल्दी से जल्दी इस दिशा में और आगे बढ़ेंगे।

Trady pace of railway projects

*424. SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA:

SHRI N.K. SINGH: ††

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Prime Minister has recently expressed serious concern over tardy pace of railway projects;

---

†† The question was actually asked on the floor of the House by Shri N.K. Singh.